भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 347 No. 40] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938 [N.C.T.D. No. 347

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य संभरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग

(खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप के आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

सं. फा. 50/212(04)/खा. एवं सं./सीए/97.—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 15 मई, 1987 की अधिसूचना एस ओ सं0 469(ई) के साथ पिठत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 16 की उपधारा (1बी) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा ए—ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली स्थित 'राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग', दिल्ली में 'न्यायपीठ संख्या 3 तथा न्यायपीठ संख्या 4' के रूप में दो और न्यायपीठों की स्थापना करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश तथा उनके नाम पर

के. आर. मीणा, सचिव-सह-आयुक्त

619 DG/2017 (1)

OFFICE OF THE COMMISSIOER FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

(DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th January, 2017

No. F. 50/212(04)/F&S/CA/97.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1B) of section 16 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), read with the Government of India, Ministry of Food and Civil Supplies, notification S. O. No. 469(E), dated the 15th May, 1987, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to establish two more benches to be known as the 'Bench No.3 and Bench No.4' in the 'State Consumer Disputes Redressal Commission', Delhi situated at 'A' Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate New Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

K. R. MEENA, Secy.-cum-Commissioner